बिजली दरों में कमी की मांग की जा रही है

बिजली दरों में कमी की मांग की जा रही है

लखनऊ | २५ जुलाई २०२५
DN Verma

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है , जिसमें प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2025-26 ट्रूप-अप पर चर्चा होनी है। इस बैठक में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बिजली दरों में कमी की मांग की जा रही है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का लगभग 33122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है , जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन बिजली कंपनियां कह रही हैं कि मामला अपीलीय ट्रिब्यून बाकी है। ऐसे में आयोग को बिजली दरों में कमी करनी चाहिए।

नोएडा पावर कंपनी के मामले में भी उपभोक्ताओं का सरप्लस निकला है , जिसमें 10% की बिजली दर में रिबेट मिल रही है। आयोग को अगले 5 वर्षों तक इस रिबेट को जारी रखना चाहिए।

इसके अलावा, बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए टैरिफ प्रस्ताव में कई खामियां हैं , जिसे आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। बिजली कंपनियों को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए और उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना चाहिए।

राज्य सलाहकार समिति की बैठक में निजीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी चाहिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष , अवधेश वर्मा, सौर विद्युत उपभोक्ता के अध्यक्ष, व महानिदेशक, एस. एम. एस. के डॉ. भरत राज सिंह तथा दीपा जनानी , फाइनेंसियल एक्सप्रेस का कहना है कि निजीकरण के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।
अंत में, आयोग को बिजली दरों में कमी करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए।

---

https://ghoomtaaina.in/a-meeting-of-the-state-advisory-committee-has-been-called-today-by-the-uttar-pradesh-electricity-regulatory-commission/